



सरकार ने कहा- मेटा जिम्मेदारी से बच नहीं सकती

बैठक में Meta ने स्वीकार किया कि कुछ खास तरह के कंटेंट को प्रमोट करने के लिए बड़ी रकम खर्च की गई। इस वजह से प्लेटफॉर्म पर अवैध कंटेंट भी प्रमोट हुआ। हालांकि, सूत्रों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस तरह के कंटेंट की बात की गई। सरकार ने Meta से कहा कि वह IT अधिनियम के तहत खुद को सिर्फ एक इंटरमीडियरी नहीं कह सकती। >> (शेष पेज 06 पर)

रांची में जंतर-मंतर जैसा धरना 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर एक ने पानी तक छोड़ा था, वांगचुक की अपील पर पिया

अनशन

तमसा संकेत, एजेंसी

रांची। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ जंतर-मंतर जैसा आंदोलन चल रहा है। 7 से ज्यादा प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं। इनमें छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न-जल छोड़ रखा था। बुधवार को सोनम वांगचुक ने देवेन्द्र से वीडियो कॉल पर बात की। उनकी अपील पर देवेन्द्र ने पानी पिया, लेकिन कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा। वहीं SDM कुमार रजत और ADM धनंजय



सोनम वांगचुक ने बुधवार को वीडियो कॉल कर छात्र देवेन्द्र महतो को पानी पिलवाया।

कुमार प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों से मिलने के लिए मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की ओर से प्रदर्शनकारियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया। >> (शेष पेज 06 पर)

फास्ट न्यूज

गडकरी से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट फौरन हटाएं

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट फौरन हटाने का आदेश दिया। साथ ही पोस्ट करने वाले यूजर्स की जानकारी भी मांगी।

जांच खुलासा

सीजेपी प्रोटेस्ट में ब्लास्ट की साजिश ख रही थी आईएसआई

अमृतसर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ चल रहे धरने के दौरान आतंकी हमले की साजिश रची थी। पंजाब पुलिस ने साजिश में शामिल चार नाबालिगों समेत कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अमृतसर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन अवैध पिस्तौल, जिंदा कारतूस, चार पेट्रोल बम, सीसीटीवी कैमरे, एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह शुक्लर ने बताया कि जिस समय जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था तभी आरोपी ट्रेन से दिल्ली पहुंचे थे।

सरकार परिसीमन बिल पर विशेष सत्र बुला सकती है

नई दिल्ली। सरकार परिसीमन पर चर्चा के लिए 16 से 18 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को संसद में राहुल, प्रियंका सहित अन्य कांग्रेस सांसदों से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि किरेन रिजिजू ने आज परिसीमन के मुद्दे पर उनसे बात की।

कंपनी ने माना चाइल्ड पोर्न कंटेंट और डीप फेक रोकने में भी नाकाम रहे पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर जुकरबर्ग ने मांगी माफी

क्षमा

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बुधवार को पीएम मोदी का फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में भारत सरकार से माफी मांगी है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी PTI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दी है। कंपनी ने यह भी माना कि उसके प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मेटेरियल, डीपफेक और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी चूक हुई है। Meta की ग्लोबल टीम ने कंपनी के ग्लोबल

अफेयर्स चीफ जोएल कैपलन के नेतृत्व में केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव और IT सचिव एस. कृष्णन से मुलाकात की। यह बैठक पिछले महीने पीएम मोदी का फेसबुक पोस्ट हटने के बाद सरकार की ओर से भेजे गए समन के बाद हुई। >> (शेष पेज 06 पर)

मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कापलान की अगुआई में एक हार्ड लेवल कमेटी ने आईटी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन से मुलाकात की।

23 जुलाई को पीएम ने वीडियो मैसेज पोस्ट किया था

23 जुलाई की रात 12 बजे X हैंडल पर पोस्ट किए गए 2.56 मिनट के वीडियो मैसेज में मोदी ने कहा- पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्रों, उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक से अब तक, पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं। हमारी जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद न हो, इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एजाम कराया। 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया। उन्होंने यह भी कहा- हम इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं। इसलिए फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है। दरअसल, यह पूरा मामला 3 मई को हुए NEET UG पेपर लीक से जुड़ा है।

स्थगन

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को अध्यक्ष सतीश महाना ने पद छोड़ने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा- कल सदन में जो हुआ, उससे मैं आहत हूँ। मेरे मन में पीड़ा है। मुझे पहली बार लगा कि या तो हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई या फिर डॉ. अंबेडकर की बात सही है कि कमी संविधान में नहीं, व्यवक्तियों में होती है। उन्होंने कहा मेरी लंबी राजनीतिक पारी अब अंतिम चरण में है। >> (शेष पेज 06 पर)

वे मुझे जेल में डालें या मार दें 2 साल बाद वर्चुअल भाषण दिया, कैमरा ऑफ था दिसंबर में बांग्लादेश लौटूंगी : शेख हसीना

संबोधन

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली/ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दो साल बाद बुधवार को लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। भाषण के दौरान उनका कैमरा बंद रहा। 25 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा-मुझे पता है कि वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या मार भी सकते हैं, फिर भी मैं दिसंबर में बांग्लादेश वापस जाऊंगी। लोगों का समर्थन मेरे लिए बहुत जरूरी है। >> (शेष पेज 06 पर)



शेख हसीना बोलीं- अवामी लीग नेताओं की हत्या हो रही, 10 हजार लोग मारे गए या लापता

शेख हसीना ने दावा किया कि अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, उन्हें गायब किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। हसीना ने कहा कि अब तक कम से कम 10 हजार लोग मारे गए हैं या लापता हैं। वहीं, 10 लाख से ज्यादा लोगों को अज्ञात आरोपी बनाकर केस दर्ज किए गए हैं।

युवाओं की बात सुनना सबसे ताकतवर हथियार : एससी भटके युवक पत्थरबाजी करते हैं, सरकार आक्रामक रवैये से बचे

सुनवाई

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कॉंग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में हिंसा को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि युवाओं की बात सुनना सबसे ताकतवर हथियार है। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को संयम रखना चाहिए। अगर कुछ भटके हुए युवक पत्थरबाजी भी करें, तब भी उन्हें समझाने और शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार को भी आक्रामक रवैया अपनाने से बचना चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की बेंच ने यह टिप्पणी रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर मनोष कुमार सोलंकी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में 20 जुलाई के 'संसद चलो' मार्च के आयोजकों यानी CJRP प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कोर्ट ने इस याचिका को इसी मामले से जुड़ी दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया। >> (शेष पेज 06 पर)



सुप्रीम कोर्ट बोला- युवाओं को काउंसिलिंग मिलनी चाहिए

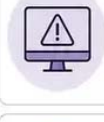
यह टिप्पणी रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर मनोष कुमार सोलंकी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में 20 जुलाई के 'संसद चलो' मार्च के आयोजकों यानी CJRP प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कोर्ट ने इस याचिका को इसी मामले से जुड़ी दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया। >> (शेष पेज 06 पर)

मेटा किन मामलों में वीडियो हटाता है?

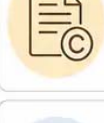
**हिंसा या हिंसा के लिए उकसाने वाला कंटेंट**

**नफरत फैलाने वाली पोस्ट (Hate Speech)**

**आतंकवाद या उग्रवाद का समर्थन**

**अश्लील या बाल यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट**

**धमकी, उत्पीड़न या बुलिंग**

**कॉपीराइट का उल्लंघन**

**फर्जी या नुकसान पहुंचाने वाली भ्रामक जानकारी**

**स्थानीय कानूनों का उल्लंघन**

**नोट- गलती से हटा कंटेंट जांच के बाद फिर बहाल कर दिया जाता है।**

यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पास सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर हमला- 'युवा, किसान और महिला विरोधी'

सपा ने रवैय के चलते वेलफेयर योजनाओं पर चर्चा नहीं हुई

सीएम योगी ने कहा- सपा के हंगामे के बीच 59 हजार करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पास हुआ। लेकिन, सपा के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर योजनाओं पर सदन में कोई चर्चा नहीं होने दी गई। उन्होंने कहा- इन्होंने (सपा) शिक्षामित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। हमारी सरकार ने शिक्षामित्रों का



विधानसभा अध्यक्ष आहत, पद छोड़ने की चेतावनी दी कहा- मैं कुर्सी के योग्य हूँ या नहीं, सोचना पड़ेगा

मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 18 हजार किया है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उनके इसी दोहरे चरित्र को उजागर किया है।

जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस

वार्ता

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में 10 जनपथ पर जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा कि 20 जुलाई को हुए कॉंग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट पर लाठी-पैलेट गन से हमला किया गया। राहुल अपने साथ चार प्रदर्शनकारी छात्र और छात्राओं को मीडिया के सामने लाए। एक छात्रा ने कहा- भारत माता की जय बोलने पर हमें देशद्रोही कहा गया। >> (शेष पेज 06 पर)



राहुल गांधी ने कहा- प्रदर्शनकारियों ने कुछ भी गलत नहीं किया। इनका लगातार शोषण हो रहा है। ये बच्चे देश के भविष्य के लिए लड़ें। इन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। लोकतंत्र के लिए ये बच्चे लड़ें, इसके लिए इनका धन्यवाद।

बयान : ब्राह्मण सम्मेलन में कृष्ण-सुदामा की दोस्ती याद दिलाई, कहा- बटुकों, शंकराचार्य का अपमान किया

पीडीए में पीड़ित, पंडित साथ-साथ : अखिलेश

‘एक डीसीएम हैं, बिना बरसात के छाता लगाते हैं’

अखिलेश ने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम वृजेश पाठक पर तंज कसा। उन्होंने कहा- एक डीसीएम हैं, बिना बरसात के छाता लगाते हैं। कहा जाता है कि उनकी एक गाई भी नहीं सुनता है। जो लोग सच्चाई जानते हैं, वह जानते हैं कि गाई की बात कोई गाई कैसे सुनेगा। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। स्वास्थ्य विभाग को आज दवाई और इलाज की जरूरत है। इस सरकार ने एंबुलेंस को बर्बाद तो किया ही है। सरकारी अस्पताल में कोई चला जाए तो संभव है उसकी जान भी न बचे। जिंदा व्यक्ति को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज देते हैं। जिसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, उसे ओटी में भेज देते हैं। ये तो अच्छा था कि उसे होश आ गया और वह वहां से भाग गया।



पर सपा प्रमुख ने कहा-इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि किसी सरकार ने शंकराचार्य को कहीं जाने से रोका हो। हमारे शंकराचार्य जी को त्रिवेणी में स्नान करने से रोका गया। उन्हें धरना तक देना पड़ा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। >> (शेष पेज 06 पर)

हेलीपैड से मंच, सुरक्षा और जनसुविधाओं तक हर व्यवस्था की समीक्षा गोविंद साहब में तैयारियों की रफ्तार तेज

निरीक्षण

बृजेंद्र वीर सिंह

तमसा संकेत, अम्बेडकरनगर। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। बुधवार को तहसील आलापुर के विकासखंड रामनगर स्थित पूर्वांचल के प्रसिद्ध धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल गोविंद साहब में मंडलायुक्त राजेश कुमार और डीआईजी सोमैन वर्मा ने कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। उनके साथ जिलाधिकारी ईशा प्रिया, पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने हेलीपैड निर्माण, मुख्य मंच, कार्यक्रम स्थल की तैयारियों और



जिलाधिकारी ईशा प्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं पर सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। लक्ष्य है कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं।

साफ-सफाई का बारीकी से जायजा लिया। इसके साथ ही पार्किंग, आवागमन मार्ग, बैठक व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, बैरिकेडिंग, विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा प्रबंधन की भी समीक्षा की गई।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने यातायात प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्था की भी समीक्षा की। कार्यक्रम स्थल तक आने वाले मार्गों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही सुरक्षा

व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली गई। पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था और स्वच्छता जैसे बुनियादी इंतजामों को भी

हर विभाग को मिली तय समय में काम पूरा करने की जिम्मेदारी

मंडलायुक्त और डीआईजी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी व्यवस्थाएं तय समयसीमा के भीतर पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सभी विभाग बेहतर समन्वय के साथ काम करें और किसी भी व्यवस्था में कमी न रहने दें। विद्युत विभाग को विशेष रूप से बिजली आपूर्ति के साथ सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान निर्बाध बिजली व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता होगी।

प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए, ताकि कार्यक्रम में आने वाले लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

किसानों के प्रशिक्षण से लेकर मिलेट्स की मार्केटिंग तक बनेगा रोडमैप आत्मा गर्वनिंग बोर्ड की बैठक में कृषि योजनाओं की समीक्षा

तमसा संकेत, संवाददाता



मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, कृषि यंत्रीकरण, फसल अवशेष प्रबंधन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन की प्रगति पर चर्चा हुई। समीक्षा के बाद योजनाओं के प्रभावी संचालन को मंजूरी दी गई। बैठक में उद्यान विभाग को बटन मशरूम उत्पादन, केला और शिमला मिर्च की खेती का विस्तार करने के निर्देश दिए गए। मत्स्य विभाग से मछली पालन के साथ मोती की खेती को बढ़ावा देने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। साथ ही जनपद में तैयार मिलेट्स उत्पादों—सावां, कोदो, रागी, ज्वार और बाजरा—की बेहतर मार्केटिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आत्मा योजना के तहत किसानों के एक्सपोजर विजिट ऐसे संस्थानों में कराए जाएं, जहां उन्हें उन्नत कृषि तकनीक, बेहतर बीज और पशुपालन की आधुनिक जानकारी मिल सके। इसके लिए कर्नाल, बरेली और बारबंकी जैसे प्रमुख कृषि एवं पशु प्रजनन केंद्रों का चयन करने को कहा गया।

फास्ट न्यूज

दुर्गा मंदिर में पूजा के बाद देवघर के लिए रवाना हुए कांवड़िये

अम्बेडकरनगर। जलालपुर में सावन माह के दौरान बुधवार को यादव चौराहा स्थित दुर्गा माता मंदिर में कांवड़ियों ने पूजा-अर्चना कर यात्रा की शुरुआत की। मंदिर में दर्शन और पूजन के बाद श्रद्धालुओं का जत्था बाबा बैजनाथ धाम (देवघर) के लिए रवाना हुआ। यात्रा शुरू होने से पहले मंदिर परिसर में कांवड़ियों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया।

सेंट पीटर्स इंटर कॉलेज में विद्यार्थी विज्ञान मंथन पर कार्यशाला

अम्बेडकरनगर। सेंट पीटर्स इंटर कॉलेज, अकबरपुर में बुधवार को विद्यार्थी विज्ञान मंथन (VVM) 2026-27 के तहत छात्र अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना, विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना और राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम में विज्ञान भारती, अवध प्रांत के राज्य समन्वयक नीरज यादव ने विद्यार्थियों को VVM की रूपरेखा से अवगत कराया।

डिस्टेंस एजुकेशन की बढ़ती उपयोगिता पर मंथन

अम्बेडकरनगर। हंसवर के चौक क्षेत्र में बुधवार को 'वर्तमान में डिस्टेंस एजुकेशन की आवश्यकता' विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता इरफान अहमद ने की, जबकि संचालन रियाज अहमद ने किया। गोष्ठी में शिक्षकों और शिक्षाविदों ने बदलते शैक्षिक परिदृश्य में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका पर अपने विचार साझा किए।

बीएनकेबी पीजी कॉलेज में नवप्रवेशी छात्रों का अभिन्यास कार्यक्रम

शैक्षणिक माहौल और सुविधाओं से कराया परिचय

तमसा संकेत, संवाददाता



डॉ. सिद्धार्थ पांडेय ने कहा कि किसी भी महाविद्यालय की मजबूती उसके पांच प्रमुख स्तंभों—प्रबंधन समिति, प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थियों—के बेहतर समन्वय पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि अभिन्यास कार्यक्रम नए छात्रों को महाविद्यालय की कार्यप्रणाली समझाने और नए वातावरण में सहज होने का अवसर देता है। उन्होंने छात्रों से नियमित उपस्थिति, अनुशासन और निरंतर अध्ययन को प्राथमिकता देने की अपील की। भूगोल विभाग के सहायक आचार्य डॉ. कमल कुमार त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को जिज्ञासु बने रहने और सीखने की निरंतर आदत विकसित करने पर जोर दिया।

मंजूरी : अम्बेडकरनगर में 14वीं वाहिनी की स्थापना की तैयारी तेज

बेवाना में सीआईएसएफ का नया टिकाना

तमसा संकेत, संवाददाता

अम्बेडकरनगर। जिले में सुरक्षा और औद्योगिक विस्तार से जुड़ी एक बड़ी परियोजना अब जमीन पर उतरने की ओर बढ़ गई है। अकबरपुर तहसील के बेवाना क्षेत्र में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की 14वीं वाहिनी स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने बटालियन के लिए प्रस्तावित भूमि खरीद को लेकर 22.50 करोड़ रुपये की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। बजट मंजूर होने के बाद अब जिला प्रशासन भूमि खरीद और अन्य प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएगा। बेवाना में सीआईएसएफ बटालियन स्थापित करने की योजना पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना के समय से चल रही थी। करीब सात वर्षों से इसके लिए जमीन चयन की



प्रस्तावित सीआईएसएफ 14वीं रिजर्व बटालियन में करीब 1025 जवानों की तैनाती होगी। यह बल जिले और आसपास के क्षेत्रों में विकसित होने वाले प्रमुख औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा में भूमिका निभाएगा।

प्रक्रिया जारी थी। सितंबर 2025 में अकबरपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर बेवाना क्षेत्र में 49.99 एकड़ भूमि का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसे पुलिस मुख्यालय के माध्यम से शासन को भेजा गया था। अब शासन की स्वीकृति मिलने के बाद परियोजना के अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जुड़ाव होने के

20.2330 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा परिसर

शासन के आदेश के अनुसार ग्राम बेवाना तहसील अकबरपुर में 20.2330 हेक्टेयर यानी करीब 49.99 एकड़ भूमि खरीदी जाएगी। इसके लिए स्वीकृत 22.50 करोड़ रुपये जिला प्रशासन के सिविल डिपॉजिट खाते में जमा कराए जाएंगे। यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से उपलब्ध कराई जाएगी और इसका उपयोग 31 मार्च 2027 तक किया जाना है। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि भूमि खरीद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तहसील स्तर के अधिकारियों के साथ जल्द बैठक की जाएगी।

कारण बटालियन के संचालन और आवागमन में भी सुविधा मिलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे लखनऊ से गाजीपुर तक औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक क्लस्टर विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। अम्बेडकरनगर के जलालपुर और बेवाना क्षेत्र में भी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

2027 तक बाल श्रम मुक्त होगा अम्बेडकरनगर श्रमिक योजनाओं की रफ्तार पर नजर

तमसा संकेत, संवाददाता



अम्बेडकरनगर। जिले में श्रमिक कल्याण योजनाओं और बाल श्रम उन्मूलन अभियान को लेकर प्रशासन ने समीक्षा तेज कर दी है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला श्रम बंधु समिति, बाल श्रम उन्मूलन समिति, जिला टास्क फोर्स और बंधुआ श्रम सतर्कता समिति की संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने की। बैठक में श्रमिकों से जुड़ी योजनाओं, पंजीकरण, श्रम कानूनों के पालन और बाल श्रम रोकने के लिए चल रहे अभियानों की स्थिति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और लंबित कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में वर्ष 2027 तक जिले को बाल श्रम मुक्त बनाने के लक्ष्य पर विशेष चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने

निर्देश दिया कि बाल श्रम रोकने के लिए नियमित जांच अभियान चलाए जाएं। बंधुआ श्रम से जुड़े मामलों में भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। समीक्षा में सामने आया कि जिले में अब तक 1,42,906 श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 2,037 नए श्रमिकों को भी जोड़ा गया है। श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत मिले 136 आवेदनों में से 125 का निस्तारण किया जा चुका है। 11 आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 990 अधिधानों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

कटोखर में ‘नल’ की राह में अटकी जल जीवन मिशन योजना पाइपलाइन बिछी, टंकी का ढांचा खड़ा लेकिन पानी की सपनाई शुरू नहीं



योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को घर-घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना था। इसके लिए गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया गया। इसके बाद पानी की टंकी के लिए ढांचा भी तैयार किया गया, लेकिन टंकी लगाने का काम आगे नहीं बढ़ सका। यही वजह है कि पूरी जलापूर्ति व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई। ग्रामीणों के अनुसार, विभाग की ओर से सितंबर 2025 तक घर-घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य बताया गया था। समय सीमा बीतने के बाद भी योजना चालू नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन बिछ जाने के बाद उन्हें लगा था कि अब पेयजल की समस्या खतम हो जाएगी, लेकिन अभी भी

उन्हें पुराने साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ग्राम सचिव गंगाराम गुप्ता ने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन की ओर से योजना को ग्राम पंचायत को अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया है। हस्तंतरित की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जलापूर्ति शुरू की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि अधूरे कार्यों के पूरा होने के बाद ही ग्रामीणों को योजना का लाभ मिल पाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल जीवन मिशन के लंबित कार्यों को जल्द पूरा कराया जाए। उनका कहना है कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा के लिए योजना का जल्द संचालन जरूरी है।

साढ़े सात फीट रास्ते की जमीन बनी विवाद की वजह

केशवपुरमेंभिड़ेदोपक्ष,मारपीटकावीडियोवायरल

तमसा संकेत, संवाददाता



अम्बेडकरनगर। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव में रास्ते की जमीन को लेकर चल रहा पुराना विवाद मंगलवार को फिर सामने आ गया। निर्माण कार्य के दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए और मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दो पक्षों के बीच रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मामले में पहले थाने पर दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया था। आरोप है कि समझौते के बाद अनिल तिवारी अपनी साढ़े सात फीट जमीन छोड़कर अपने हिस्से में निर्माण करा रहे थे। इसी दौरान अमितेश कुछ अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माणाधीन

दीवार हटाने लगे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। पहले काहसुनी हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गांव निवासी अनिल तिवारी और अमितेश के बीच रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मामले में पहले थाने पर दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया था। आरोप है कि समझौते के बाद अनिल तिवारी अपनी साढ़े सात फीट जमीन छोड़कर अपने हिस्से में निर्माण करा रहे थे। इसी दौरान अमितेश कुछ अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माणाधीन

योगी सरकार का हर पात्र महिला को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के लिए घर-घर अभियान शुरू चलाया जाएगा ‘परिवार संतुष्टिकरण अभियान’

निर्देश

■ विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती

■ सभी पात्र स्वयं सहायता समूहों के तत्काल खुलवाए जाएंगे बैंक खाते

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मेगा प्लान



जाएगी, जो अभी तक स्वयं सहायता समूहों या ग्रामीण आजीविका मिशन से नहीं जुड़े हैं। अभियान का उद्देश्य हर पात्र महिला को स्वरोजगार, बैंकिंग सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से जोड़कर आर्थिक

अभियान के दौरान विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी घर-घर जाकर सर्वे करेंगे और ऐसे परिवारों की पहचान करेंगे, जहां महिलाएं अभी स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा नहीं हैं। सर्वे के आधार पर उन्हें समूहों से जोड़ा जाएगा ताकि वे बचत, ऋण, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार

जब अधिक से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ेंगी तो गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। छोटे-छोटे घरेलू उद्योग, कृषि आधारित गतिविधियां, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और अन्य स्वरोजगार के माध्यम विकसित होंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और महिलाओं की आय में भी वृद्धि होगी।

योगी सरकार चाहती है कि प्रत्येक पात्र महिला को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उसकी आय बढ़ाई जाए और ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर

स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते भी खुलेंगे

योगी सरकार ने अभियान के दौरान सभी पात्र स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते तत्काल खुलवाने के निर्देश दिए हैं। इससे समूहों को सरकारी वित्तीय सहायता, बैंक ऋण और अन्य योजनाओं का लाभ सीधे मिल सकेगा। बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ने के बाद ग्रामीण महिलाओं के लिए छोटे उद्यम शुरू करना और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करना आसान होगा।

10 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे एक करोड़ 19 लाख से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं। इन समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को केवल बचत और ऋण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें उद्यमी बनने का अवसर भी दिया है।

पराविधिक स्वयं सेवकों द्वारा जन जागरूकता चलाया जा रहा अभियान

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ कुँवर मिश्रे सिंह कुशवाहा ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 12 सितम्बर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पराविधिक स्वयं सेवकों द्वारा जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ श्री मलखान सिंह के मार्गदर्शन में तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी श्री प्रकाश तिवारी के निर्देशन में जनपद की दीवानी न्यायालय परिसर, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पारिवारिक न्यायालय, कामशियल कोर्ट, भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, समस्त तहसीलों एवं



अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पराविधिक स्वयं सेवकों द्वारा जागरूकता शिविर के माध्यम से लोक अदालत संबंधी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बैंक ऋण वसूली, श्रम, विद्युत, राजस्व, पारिवारिक, चेक बाउंस, प्री-लिटिगेशन, आरबीट्रेशन तथा अन्य सुलभ योग्य वादों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है।

फास्ट न्यूज

लखनऊ में डॉक्टर की पत्नी फंदे से लटकी मिलीं

लखनऊ । लखनऊ में मंगलवार शाम करीब 4 बजे सीतापुर से ड्यूटी कर घर लौटे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सहायक को उनकी पत्नी कमरे में फंदे से लटकी मिलीं। उन्होंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा। कमरे के अंदर उनकी पत्नी पंखे से फंदे के सहारे लटकी मिलीं।

50 साल के व्यक्ति को महिला ने 35 चप्पल जड़े

लखनऊ । लखनऊ में छेड़खानी के आरोप में 38 साल की महिला ने 50 साल के व्यक्ति को डेढ़ मिनट में 35 से ज्यादा चप्पल जड़े। वह भागने लगा तो उसे करीब 500 मीटर तक दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। मौके पर भीड़ जुड़ गई। आरोपी ने महिला से हाथ जोड़कर माफी मांगी। इस पर महिला ने उसे माफ कर दिया और पुलिस से शिकायत नहीं की। घटना बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे कैसरबाग थाना क्षेत्र के लालबाग में हुई। घटना का वीडियो सामने आया है। महिला ने कहा कि वह अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहती हैं। लेकिन वह चाहती हैं कि महिलाओं के साथ अप्रदत्ता करने वालों का तत्काल विरोध होना चाहिए।

एलडीए रिश्वत कांड में बारबंकी में वसूली हुई नाकाम

लखनऊ । एलडीए के 7.5 लाख रुपए के रिश्वत कांड की जांच में नया खुलासा हुआ है। बिजिलेंस और एलडीए से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, कथित बिचौलिया श्रृंग कुमार पहले से एनआरआई कारोबारी जितेंद्र नारायण को निशाना बना रहा था। सूत्रों के अनुसार, बारबंकी में निर्माण कार्य के दौरान कारोबारी से वसूली की कोशिश की गई थी, लेकिन यह सफल नहीं हुई।

आयोजन : उत्तर प्रदेश लगभग 38.8 मिलियन मिट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ देश में प्रथम स्थान पर

नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत 2.25 लाख रोजगार सृजित हुए

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों में दुग्धशाला विकास विभाग एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय जनपदीय स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव-2026 का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ तथा दुग्धशाला विकास विभाग मुख्यालय से दुग्ध आयुक्त श्रीमती धनलक्ष्मी के0 का संबोधन एवं विभागीय योजनाओं से सम्बन्धित विडियो को वेब लिंक के माध्यम से प्रसारित किया गया।



कान्क्लेव को संबोधित करते हुए दुग्ध आयुक्त ने कहा कि वर्ष 2024-25 में भारत लगभग 248 मिलियन मिट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसमें उत्तर प्रदेश लगभग 38.8 मिलियन मिट्रिक टन दुग्ध उत्पादन एवं लगभग 16 प्रतिशत योगदान के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तीकरण, रोजगार सृजन एवं किसानों की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम है।

आधुनिक डेयरी तकनीकों वैज्ञानिक पशुपालन, पशु स्वास्थ्य, संतुलित पशु आहार तथा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई

दुग्धशाला विकास विभाग की स्वर्ण जयंती वर्ष पर प्रदेश के सभी जनपदों में जनपदीय स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव - 2026 का आयोजन किया गया कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में 2100 नव चयनित मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना, 1500 से अधिक मिनी नन्दनी कृषक समृद्धि योजना तथा 450 से अधिक नन्दनी कृषक समृद्धि योजना के लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किये गये

उन्होंने बताया कि नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से कुल 17,994 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है तथा

समितियों के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की

कॉन्क्लेव में जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों, पशुपालन एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों, दुग्ध संघों के प्रतिनिधियों, प्रगतिशील दुग्ध उत्पादक किसानों, पशुपालकों, स्वयं सहायता समूहों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने आधुनिक डेयरी तकनीकों वैज्ञानिक पशुपालन, पशु स्वास्थ्य, संतुलित पशु आहार तथा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।

दुग्ध आयुक्त ने सभी हितधारकों से विभागीय योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने, आधुनिक एवं वैज्ञानिक पशुपालन तकनीकों को अपनाने तथा प्रदेश के डेयरी क्षेत्र को और अधिक समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाने में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

4,951 प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी समितियों के गठन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 2.25 लाख रोजगार सृजित हुए हैं।

लखनऊ में महिला की संदिग्ध हालत में मौत

दुग्गा। पारा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने पति, सास-ससुर समेत सात लोगों पर दहेज के लिए प्रमादित करने और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आजमगढ़ निवासी हबीबुर रहमान ने पारा थाने में दर्ज कराई गई तहरीर में बताया कि उसकी 25 वर्षीय बहन नैय्यबा खातून का निकाह 22 फरवरी 2025 को पारा क्षेत्र की जनता विहार कॉलोनी फेज-2, सलेमपुर पटौरा निवासी अब्दुल रहमान खान से हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति, सास, ससुर और अन्य ससुरालीन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसका लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करते थे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। तहरीर के अनुसार, ससुराल पक्ष ने कारोबार के लिए रुपये की मांग की थी। बेटी का घर बसाने की उम्मीद में मृतका की मां ने 12 अक्टूबर 2025 को दो लाख रुपये चेक और तीन लाख रुपये नकद दिए थे।

‘हर घर तिरंगा अभियान 2026’ का आयोजन

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ । प्रदेश के समस्त जनपदों में 09 से 17 अगस्त, 2026 के बीच “हर घर तिरंगा अभियान-2026” का आयोजन किया जाएगा। इस हेतु अपर मुख्य सचिव पर्यटन एवं संस्कृति की ओर से समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, उ0प्र0 शासन तथा समस्त जिलाधि-कारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी करा दिए गए हैं। जिला स्तर पर इस आयोजन हेतु कार्यक्रम का समन्वय संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। जारी शासनादेश में हर घर तिरंगा अभियान-2026 को चरणबद्ध रूप से आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण 06 अगस्त से 08 अगस्त, 2026 के दौरान स्कूलों की दीवारों और बोर्डों को तिरंगा से प्रेरित कलाकृतियां सजायी जाएगी। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय



हर घर तिरंगा अभियान को प्रदेशव्यापी बनाते हुए इसे जनआंदोलन एवं राष्ट्रगौरव का प्रतीक बनाया जाए-जयवीर सिंह

द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप मुख्य कार्यक्रम शैक्षणिक, संस्थानों, सरकारी भवनों, शॉपिंग मॉल, रेलवेस्टेशन, हवाई अड्डा, बस अड्डा, सार्वजनिक उद्यान आदि चिन्हित स्थानों पर किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों, कालेजों और सार्वजनिक स्थानों आदि पर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

अभिभावकों की सहमति से तैयार की जा रही डिजिटल आईडी एक संस्थान से दूसरे संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया होगी सुगम

■ विधान परिषद में 'अपार आईडी' योजना पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने रखा सरकार का पक्ष

■ 12 डिजिट की अपार आईडी से छात्र-छात्राओं के सभी शैक्षिक प्रपत्र जीवन भर रहेंगे सुरक्षित और डिजिटली वेरीफाइड



सरकार का पक्ष रखा तथा सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनकल्याण, सुशासन एवं समग्र विकास के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। विधान परिषद में चर्चा के दौरान सहभाग करते हुए प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर

को एक ही स्थान पर सुरक्षित रखने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा छात्रों के हित में 'अपार (APAAR) आईडी' योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे के लिए 12 डिजिट की एक यूनिक आईडी बनाई जाती है। यह डिजिटल आईडी बच्चे के लिए जीवन भर उपयोगी साबित होगी, जिससे उसके सभी शैक्षिक प्रपत्र डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे और किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जाने पर तत्काल डिजिटल वेरिफिकेशन संभव हो सकेगा। इससे छात्र-छात्राओं के एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरण एवं प्रवेश की प्रक्रिया भी बेहद सुलभ होगी।

12 रिजर्व सीटें क्यों खत्म कराना चाहते हैं प्रदर्शनकारी, मांगें क्यों नहीं मान रही सरकार पीओके पाकिस्तान के लिए बना परेशानी

चुनौती

मुजफ्फराबाद, एजेंसी

पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर कई बार युद्ध हो चुका है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ कश्मीर विवाद को सबसे बड़ा मुद्दा माना। इस वजह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के लोगों की अपनी परेशानियों पर कम ध्यान दिया गया। अब वहां हालात ऐसे हैं कि सरकार के लिए उनकी आवाज दबाना मुश्किल हो रहा है।

महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल चुका है। इसे कई वर्षों में पाकिस्तान सरकार के सामने PoK से उठी सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है।



■ PoK में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। इस दौरान राजधानी मुजफ्फराबाद में सिव्थीरि फोर्स गश्त करते हुए दिखाई दी।

आंदोलनों के सफल होने से JAAC का जनाधार बढ़ा। अब संगठन महंगाई के मुद्दे से आगे बढ़कर PoK को ज्यादा स्वायत्तता और राजनीतिक अधिकार देने की मांग कर रहा है। सबसे बड़ी मांग PoK विधानसभा की 45 सीटों में से 12

पीओके में आंदोलन की कमान किसके हाथ में है?

PoK में आंदोलन का नेतृत्व जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) कर रही है। इसका गठन 2023 में हुआ था। इसमें व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नेता शामिल हैं। शुरुआत में संगठन ने महंगी बिजली और आटे की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। 2024 और 2025 में हुए प्रदर्शनों के बाद पाकिस्तान सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने बिजली की दरें कम कीं और आटे पर सब्सिडी दी। इसके बाद PoK में आटा पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों की तुलना में काफी सस्ता मिलने लगा।

लॉन्ग मार्च पर रोक, कई नेता गिरफ्तार हुए

JAAC ने 9 जून को रावलकोट से राजधानी मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। रावलकोट को JAAC का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यह जगह LoC से करीब 20 मील दूर है। लॉन्ग मार्च होने से पहले ही 5 जून को पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिया। कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद आंदोलन नहीं रुका। रावलकोट में समर्थकों ने कई हफ्तों तक धरना जारी रखा, जबकि दूसरी तरफ सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत भी चलती रही।

पिछले सप्ताह इलाके में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पाकिस्तान सरकार ने PoK के कई हिस्सों को लगभग बाहरी दुनिया से काट दिया है। पूरे इलाके में कई हफ्तों से इंटरनेट सेवा बंद थी। इसका असर सिर्फ मोबाइल और सोशल मीडिया पर नहीं पड़ा, बल्कि बैंक और ATM सेवाएं भी प्रभावित हुईं।

फास्ट न्यूज

यूएस में भारत की बेटी का कमाल

लॉस एंजेलिस। लॉस एंजेलिस में रहने वाली भारतीय मूल की जान्हवी गुप्ता केवल फिल्म फेस्टिवल्स में ही नहीं, बल्कि अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बना रही हैं। उनकी फिल्में लगातार पुरस्कार जीत रही हैं और अमेरिका के निर्माता व निर्देशक उनके काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। फिल्म निर्माता नेनन न्यूके जान्हवी गुप्ता की तारीफ करते हुए कहते हैं, 'वह अपने साथ काम करने वालों से कहीं आगे के स्तर पर काम करती हैं।

दुबई में तबाइतोड़ हमलों से धुआं-धुआं हुआ शहर

दुबई। जेबेल अली इंडस्ट्रियल क्षेत्र में 20 मिनट के भीतर सात धमाके हुए, जिनके बाद आसमान में काला धुआं दिखाई दिया। वीडियो बनाने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार किए गए। घटना के कारण पर सस्पेंस है। हालांकि मिसाइल हमले के दावे हुए हैं। दुबई के जेबेल अली इंडस्ट्रियल क्षेत्र में कई धमाकों हुए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में रात के आसमान में धुएं के घने गुबार छापे हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान की मेहर समाचार एजेंसी ने अमीराती अधिकारियों के हवाले से बताया कि 20 मिनट के अंदर कम से कम सात धमाके हुए।

खाड़ी देशों में हर सप्ताह तीन भारतीयों की मौत

दुबई। दुबई में एक कार शोरूम में गैस सिलेंडर विस्फोट में केरल के एक भारतीय प्रवासी की मौत हो गई। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार है। गल्फ न्यूज अखबार के अनुसार, केरल के कोल्लम जिले के रहने वाले 27 वर्षीय शिजिन पॉल की सोमवार को शेख जायद रोड स्थित एक कार शोरूम में हुए विस्फोट में मौत हो गई।

घटना: आग के कारण लोग घर छोड़कर भागे, 150 बचाए गए, 30 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, बिजली काटी गई

साओ पाउलो के केमिकल प्लांट में भीषण आग के बाद कई धमाके

साओ पाउलो, एजेंसी

ब्राजील के साओ पाउलो में भीषण हादसा हुआ है। यहां के एक केमिकल प्लांट में भीषण आग लगने के बाद कई धमाके हुए, जिससे घबराए लोग अपना घर छोड़कर भाग गए। आग पर काबू पाने के लिए 30 दमकल गाड़ियां और 60 से ज्यादा दमकलकर्मी जुटे हुए हैं। आग लगने से घने धुएं और आग की लपेट आसमान में काफी ऊपर तक उठ रही है और 150 लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ग्रेटर साओ पाउलो के इटाक्वाक्वेसेटुबा में एक सॉल्वेंट प्लांट में ये आग स्थानीय समय के अनुसार दोपहर करीब 3 बजे लगी।



साओ पाउलो की मिलिट्री फायर ब्रिगेड ने कहा, 'इअब तक पीड़ितों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पता चला है कि आस-पास के इलाके में बिजली काट दी गई है और 150 लोगों को सुरक्षित बाहर

निकाला गया है। प्रभावित कंपनी क्वेमा क्विमिका (Quema Química) है जो सॉल्वेंट्स और पॉलिएस्टर रजिन का उत्पादन और विपणन करती है। फैक्ट्री में सॉल्वेंट स्टोर करने के लिए 24 टैंक हैं,

100 फीट से ज्यादा ऊंचा उड़ता दिखा धुआं घटनास्थल के वीडियो और तस्वीरों में फैक्ट्री से उड़ती आग की विशाल लपेटें और 100 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक उड़ता घना धुआं दिखाई दे रहा है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि घटनास्थल पर कई धमाके हुए हैं।



आग में घी का काम कर रहे सॉल्वेंट टैंक

एक वीडियो में जमीन से मैनहोल का ढक्कन फटकर उछलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस धमाके की वजह से वहां से गुजर रहा एक व्यक्ति गिर पड़ा। प्लांट में सॉल्वेंट के 24 टैंक हैं और ये आग में घी का काम करते हैं। इसके अलावा, आग एक ऐसे औद्योगिक इलाके में लगी है जहां बहुत ज्यादा ज्वलनशील उत्पाद रखे हैं, जिससे धमाके का खतरा और बढ़ गया है।

जिनमें से हर एक की क्षमता लगभग 31 क्यूबिक मीटर है। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने का काम जारी रखे हुए हैं।

बिना उकसावे के हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा यमन जहाज हमले पर विदेश मंत्रालय की दो टूक

सना, एजेंसी

विस्फोटकों से भरी एक नाव द्वारा किए गए हमले के बाद, यमन के पश्चिमी तट के पास लाल सागर में भारत के झंडे वाला एक मालवाहक जहाज डूब गया। इस जहाज पर चालक दल के 14 सदस्य सवार थे, जिनमें 13 भारतीय और एक यमनी नाविक था। यमनी बलों द्वारा सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। MSV फैज नूर ओलिय्या नाम के जहाज पर हथूथी के कब्जे वाले बंदरगाह शहर होदेइदाह से लगभग 13 नॉटिकल मील दक्षिण में हमला किया गया। यमन की नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स, जिसके गाइड्स ऑफ द रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाता है, ने एक बयान में कहा कि कोस्ट गार्ड और नेवी की यूनिट्स ने नाविकों को बचाने के लिए एक



जॉइंट ऑपरेशन चलाया। उन्होंने हमले के लिए हथूथी ग्रुप को भी जिम्मेदार ठहराया। भारत ने एक बयान में यमन के समुद्री इलाके के पास जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। केंद्रीय जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि उन्होंने डायरेक्टर जनरल मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिया है कि वे सभी एजेंसियों के साथ मिलकर उस इलाके में भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बचाए गए कू को ज़रूरी मदद देने के लिए तुरंत कदम उठाएं।

प्लास्टिक के नोट अप्रैल मई 2027 में आएंगे



नई दिल्ली, एजेंसी

पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट अगले साल अप्रैल-मई के बीच लॉन्च होंगे। यह जानकारी RBI की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी, यानी MPC की तीन दिन चली बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में कम वैल्यू के पॉलीमर करेंसी नोट जारी किए जाएंगे। इनका मार्केट में सर्कुलेशन और इस्तेमाल सबसे

ज्यादा होता है। उन्होंने कहा-दुनिया के कई देशों जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पॉलीमर करेंसी नोट 30 साल से भी अधिक समय तक सफलतापूर्वक उपयोग में रहे हैं। भारत में कागजी नोट, विशेषकर 10, 20 और 50 के छोटे नोट, बहुत जल्द गंदे हो जाते हैं या फटने लगते हैं। गवर्नर ने कहा- पॉलीमर नोट आने से इनकी उम्र बढ़ेगी, पानी या नमी से ये खराब नहीं होंगे और बार-बार नए नोट छापने का सरकारी खर्च भी कम होगा।

गूगल और मेटा पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

यह नया प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन को हाल ही में मिली एक कानूनी हार के बाद आया है। अमेरिकी फ़ेडरल अपील्स कोर्ट ने नए H-1B वीजा पर प्रस्तावित 1,00,000 डॉलर की फीस को रद्द करने वाले निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

आमतौर पर H-1B वीजा वाले कर्मचारियों को शुरुआती तीन साल के प्रवास के बाद वीजा बढ़वाने की जरूरत होती है। इसलिए प्रस्तावित बदलावों से उन कंपनियों के लिए इमिग्रेशन से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं जो विदेशी टैलेंट (जिसमें भारतीय पेशेवर भी शामिल हैं) पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं।

क्या कहता है मौजूदा नियम?

अमेरिका में मौजूदा नियमों के तहत जिन कंपनियों में 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं और उनमें से आधे से ज्यादा के पास H-1B या L-1 वीजा है तो उन्हें शुरुआती याचिका दाखिल करते समय या किसी कर्मचारी के नियोक्ता बदलने पर H-1B याचिकाओं के लिए अतिरिक्त 4,000 डॉलर और L-1 याचिकाओं के लिए 4,500 डॉलर का भुगतान करना पड़ता है। नियम में कहा गया है, 'इडीएएस नियमों में बदलाव और स्पष्टीकरण कर रहा है ताकि यह साफ किया जा सके कि 9-11 रिस्पॉन्स फीस सभी H-1B और L-1 एक्सटेंशन याचिकाओं पर लागू होगी।

406,685 H-1B याचिकाओं को मंजूरी दी गई। इनमें से 71 प्रतिशत मंजूरियां (जो कुल 291,542 अर्जियों के बराबर हैं) प्रोग्राम में पहली बार शामिल होने वालों के

नेतन्याह ने गाजा पर ट्रंप की योजना से जताई असहमति इजरायली सेना नहीं हटेगी पीछे

यरुशलम, एजेंसी

गाजा में सामान्य स्थिति की बहाली को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना से इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतन्याहू ने असहमति जता दी है। नेतन्याहू की असहमति हमास और अन्य सशस्त्र संगठनों के सभी हथियारों को डालने और इजरायली सेना को गाजा से वापसी को लेकर है। नेतन्याहू ने गाजा को हथियारविहीन बनाने की शर्त की याद दिलाई है। कहा है कि उसके बिना गाजा में येलो लाइन से इजरायली सेना का पीछे हटना संभव नहीं है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास के सभी हथियार डालने और गाजा के हथियारविहीन होने से पहले फलस्तीनी क्षेत्र की पुनर्निर्माण योजना को क्रियान्वित करने के विचार से वह पूरी तरह से असहमत हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा,



हाल में काहिरा में हमास के हथियार डालने के समझौते को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे पता चलेगा कि गाजा में किस कार्य के लिए क्या समय निश्चित किया गया है। नेतन्याहू से पहले सोमवार को इजरायल की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के सदस्य कैबिनेट मंत्री एली कोहेन साफ कर चुके हैं कि गाजा पर हमले बंद नहीं होंगे और न ही वहां से इजरायली सेना हटेगी। हमास के पूरी तरह से हथियार डालने और उसका अस्तित्व खत्म करने पर इजरायल ने समझौता किया है।

तमसा संकेत

tamsa.news@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्यादेवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेप्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ- 226 029 (उ०प्र०) से मुद्रित कराकर तमसा संकेत भवन शहजादपुर, अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर (उत्तर प्रदेश) (पिन कोड- 224122) से प्रकाशित

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं है।

मो0- 9415799533

R.N.I. NO. 64107/96